



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/ श्रावण 31, 1939

No. 219]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

**विषय :** यूरोपीय संघ और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नायलान फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**सं. 14/33/2016-डीजीएडी.**—मैं. जेसीटी लिमिटेड, मैं. गुजरात पालीफिल्म्स प्रा. लि., मैं. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि., मैं. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा. लि. और एवाईएम सिंटेक्स (जिसे पहले वेलस्पन सिंटेक्स के नाम से जाना जाता था) (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक कहा गया है) द्वारा संगत सूचना के साथ समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे आगे याचिका कहा गया है) दायर किया गया है जिसमें यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलान फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं। इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद नायलान का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पोलिआमाइड यार्न के रूप में भी जाना जाता है। नायलान फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है जिसे कार्बनिक मोनोमर्स के पालीमराजेशन से उत्पादित किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद में नायलान के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न या पालीआमाइड्स, सिलाई धागे से इतर जैसे फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रानयार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रान यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), उच्च ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), टैक्सचर्ड यार्न - ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड और डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टिपल, फोल्डेड या केबल्ड शामिल हैं जो सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402 के अधीन अध्याय 54 के भीतर वर्गीकरण योग्य हैं। इस उत्पाद में नायलान फिलामेंट यार्न या पालीआमाइड यार्नों की सभी किस्में जैसे फ्लैट/टैक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी-डल/ फुल-डल (या उसकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (या उसकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टिपल/फोल्डेड/केबल्ड (या उसकी किस्में), चाहे आकार में हों अथवा नहीं, शामिल हैं परंतु इनमें सीमाशुल्क उपशीर्ष 5402.10 के अधीन वर्गीकृत नायलान के उच्च तन्यता वाले यार्न शामिल नहीं हैं। एनएफवाई के प्रमुख अंतिम प्रयोगों में घर की साज-सज्जा और औद्योगिक अनुप्रयोग के क्षेत्र जैसे पर्दे, सिलाई और बुनाई का धागा, अपहोल्ट्री, फिशनैट आदि हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

5. नायलान फिलामेंट यार्न के विभिन्न प्रकार जैसे फ्लैट यार्न, क्रिम्पड यार्न, आंशिक रूप से ओरिएंटेड यार्न, फुली ओरिएंटेड यार्न/फुली ड्रान यार्न (एफओवाई/एफडीवाई भी वर्तमान जाँच के दायरे के भीतर हैं)। ऐसे सभी मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न जिनमें नायलान या पालीमाइड्स या मोनो फिलामेंट यार्न न हो, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं।

6. घरेलू उद्योग ने डेनियर, चमक, ग्रेड आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर पीयूसी के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का सुझाव दिया है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के बीच उचित तुलना के प्रयोजनार्थ पीसीएन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

घरेलू उद्योग तथा उत्पादक(कों)/निर्यातक(कों) से ऊपर यथा परिभाषित पीयूसी के अधीन आने वाले उत्पादों की सभी पहचान योग्य/सुमान्य उप श्रेणियों के लिए ब्यौरे/आकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा। उत्पादक(कों)/निर्यातक(कों) और घरेलू उद्योग से ब्यौरे/आकड़े प्राप्त करने के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या पीयूसी को पीसीएन के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाए अथवा नहीं और यदि हां, तो पीसीएन के लिए कौन-से मापदंड प्रयोग किए जाएं।

#### ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. जेसीटी लिमिटेड, मै. गुजरात पालीफिल्म्स प्रा. लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि., मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा. लि. और एवाईएम सिंटेक्स (जिसे पहले वेलस्पन सिंटेक्स के नाम से जाना

जाता था) द्वारा दायर किया गया है। इस उत्पाद के पाँच अन्य भारतीय उत्पादक हैं अर्थात् सालासर, जेपीबी फाइबर, गुप्ता सिंथेटिक्स लि., सेचुरी एंका और ओरिलोन इंडिया प्रा. लि. हैं। सभी अन्य उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों के उत्पादन का भारत में उत्पादित समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। इस प्रकार, यह निर्धारित होता है कि आवेदन घरेलू उद्योग की द्वारा या उसकी ओर से किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अधीन स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है। इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग हैं।

#### ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के अनुसार तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के संबंध में अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की तुलना से पता चलता है कि घरेलू उत्पाद द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान है।

#### घ. शामिल देश और निर्धारित न्यूनतम सीमा

9. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं।

#### ड. सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में किसी विश्वसनीय सूचना के अभाव में संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य का अनुमान भारत में उत्पादन लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके लगाया गया है।

#### च. निर्यात कीमत

11. कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत को डीजीसीआईएस द्वारा जारी सौदा-वार आकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। मालभाड़े, बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े, बैंक प्रभारों और कमीशन आदि के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

#### छ. पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

#### ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और खपत, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और मालसूची के संबंध में कार्यनिष्पादन पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से कथित पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

### जाँच की शुरूआत

14. प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत का उचित ठहराते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं।

### ज. जांच अवधि

15. आवेदकों द्वारा वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 तक की जाँच अवधि प्रस्तावित है। तथापि प्राधिकारी ने अक्टूबर 2015 - मार्च 2017 (18 महीने) की अवधि जाँच अवधि के रूप में ली गई है। क्षति जाँच में 2013-14, 2014-15 और 2015-16 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### ट. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें और प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर अपने विचारों से अवगत करा सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**  
**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**  
[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (प्राधिकारी की वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

### ठ. समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### ड. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख).

अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय अंश और अगोपनीय अंश की दो-दो (2) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा अवश्य प्रस्तुत की जाएं।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **ण. असहयोग**

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2017

**Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Nylon Filament Yarn (Multi Filament)” originating in or exported from European Union and Vietnam.**

**No. 14/33/2016-DGAD.**—M/s. JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd, M/s Prafful Overseas Pvt. Ltd & AYM Syntex (Formerly known as Welspun Syntex) (hereinafter referred to as ‘petitioner companies’ or “the applicants”) have filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning imports of ‘Nylon Filament Yarn (Multi Filament)’ (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union and Vietnam (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

**A. Product under consideration and like article**

3. The product under consideration in the present investigation is “Synthetic Filament Yarn of Nylon” also known as Polyamide Yarns. Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration is multi-filament.

4. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi-dull/full-dull (or variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized, but *excludes* high tenacity yarn of nylon classifiable under customs sub-heading 5402.10. The subject goods are classified under Chapter 54 of the Custom Tariff Act. The major end uses of NFY are in home furnishing and industrial application areas such as curtains, sewing and embroidery thread, upholstery, fishnets etc. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

5. Various types of Nylon Filament Yarn such as Flat yarn, crimped yarn, partially oriented yarn, Fully Oriented yarns / Fully Drawn Yarns (FOY/FDY are also within the scope of the present

investigation. Specifically excluded from the scope of product under consideration are all man-made filament yarns not having Nylon or Polyamides and mono filament yarn.

6. Domestic Industry has suggested Product Control Numbers(PCNs) for PUC based on various parameters like denier, lustre, grade etc. However, the Designated Authority has not taken any final decision on PCNs for the purpose of fair comparison between the products produced by Foreign Producers and Domestic Industry.

Domestic industry as well as Producer(s)/Exporter(s) would be requested to submit details/data for all the identifiable/ well recognised sub categories of products falling under the PUC as defined above. Only after getting the details/data from Producer(s)/Exporter(s) and the Domestic Industry, a final view would be taken on whether to sub classify the PUC into as PCNs or not and if yes, which parameters to use for PCNs.

### **B. Domestic Industry & Standing**

7. The application has been filed by M/s JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd, M/s Prafful Overseas Pvt. Ltd & AYM Syntex (Formerly known as Welspun Syntex). There are five other Indian producers of the product, namely, Salasar,JPB Fiber, Gupta Sythetics Limited, Century Enka, and Oriilon India Pvt Ltd. All the other producers have supported the application. It is noted that the production by the applicants constitute 'a major proportion' of Indian production of the like product produced in India. Further, petitioners have neither imported the subject goods nor are they related to any importer or exporter of the subject goods. It is, thus, determined that the application has been made by and on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the applicants constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

### **C. Like Article**

8. The applicants have claimed that there is no known difference in product produced by the applicants and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. It has been claimed by the domestic industry that comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product show that the subject goods produced by the domestic industry are similar to the subject goods imported from subject countries in terms of essential product properties.

### **D. Countries involved and de minimis limits**

9. The countries involved in the present investigation are European Union and Vietnam (hereinafter referred to as 'Subject Countries').

### **E. Normal value in subject countries**

10. The applicant has claimed that in the absence of the availability of reliable information of the domestic prices of the subject goods in the subject countries in the public domain, the normal value in subject countries have been estimated on the basis of cost of production in India, duly adjusting for selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

**F. Export Price**

11. Export Prices at ex-factory level have been determined considering volume and value of imports as per data released by DGCIS transaction wise. Price adjustments have been claimed on account of freight, insurance, port expenses, inland freight, bank charges and commission etc., on the basis of best available information.

**G. Dumping Margin**

12. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

**H. Evidence of Injury and Causal Link**

13. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact on profitability, return on capital employed, cash flow, performance on account of, market share and inventories of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

**I. Initiation of investigation**

14. The authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry and causal link between alleged dumping and injury, to justify initiation of anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry. Accordingly, the authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules.

**J. Period of investigation (POI)**

15. The period of investigation proposed by the applicants is April 2015-September 2016, however, the Authority has taken the period of investigation as October 2015 – March 2017 (18 Months). The injury investigation period shall cover the periods 2013-14, 2014-15 and 2015-16 and the period of investigation.

**K. Submission of Information**

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,**  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building,  
5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.  
[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) ) within the time limit set out below.

**L. Time limit**

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter within two weeks from the date of this notification and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within 40 days from the date of publication of this notification.

**M. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis**

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**N. Inspection of Public File**

26. In terms of rule 6(7) of Anti-Dumping Rules any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

**O. Non-cooperation**

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority